CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

+91 7428706078
info@cedsi.in

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

डेयरी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा लाने के लिए टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड ने एनडीडीबी के साथ साझेदारी की।

टाटा पावर की सहायक कंपनी टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड ने भारत की डेयरी मूल्य श्रृंखला के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह सहयोग डेयरी क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों में सौर माइक्रोग्रिड प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके स्थिरता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

प्रमुख पहलों में डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस), बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) और मिल्क चिलिंग सेंटरों को सौर ऊर्जा से संचालित करना शामिल है, जिससे क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न और ऊर्जा लागत को कम करने में मदद मिलती है।

साझेदारी का उद्देश्य डेयरी उत्पादन और प्रसंस्करण में स्थायी ऊर्जा समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए एनडीडीबी के चल रहे प्रयासों का समर्थन करना है, जिससे सहकारी डेयरी मॉडल को और मजबूत किया जा सके जो देश के ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

पीएम मोदी इनोवेटिव डेयरी फार्मिंग टेक्नोलॉजीज लॉन्च करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेयरी फार्मिंग दक्षता बढ़ाने और आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल का अनावरण करेंगे। इनमें से प्रमुख है भारतीय नस्लों के लिए डिज़ाइन की गई एकीकृत जीनोमिक चिप की शुरूआत, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बैल और दुधारू मवेशियों की पहचान करने में मदद करेगी।

सेक्स-सॉर्टेड वीर्य उत्पादन तकनीक से लागत में काफी कमी आएगी, जिससे किसानों के लिए मादा बछड़े पैदा करना अधिक सुलभ हो जाएगा। सेक्स-सॉर्टेड तकनीक के मौजूदा आयात की कीमत 1,000 रुपये प्रति खुराक है, लेकिन नई स्थानीय पद्धति से यह घटकर 200 रुपये हो जाएगी।

इन प्रगतियों का लक्ष्य गैर-उत्पादक आवारा जानवरों की संख्या को कम करते हुए अधिक टिकाऊ डेयरी क्षेत्र बनाना है। मोदी पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिससे 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह व्यापक समर्थन भारत में कृषि समुदाय को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पीएम ने कृषि, पशुपालन क्षेत्रों के लिए 23,300 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू कीं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में कृषि और पशुपालन को बढ़ाने के उद्देश्य से ₹23,300 करोड़ की महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। नांदेड़ हवाईअड्डे पर पहुंचकर मोदी ने सबसे पहले पोहरादेवी में जगदंबा माता मंदिर में पूजा की और संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की विरासत का सम्मान किया।

बाद के एक कार्यक्रम में, उन्होंने लगभग 9.4 करोड़ किसानों को कुल मिलाकर ₹20,000 करोड़ की पीएम-किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त वितरित की। इससे योजना के तहत जारी कुल राशि लगभग ₹3.45 लाख करोड़ हो गई है।

मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत ₹1,920 करोड़ की 7,500 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही ₹1,300 करोड़ के कारोबार वाले 9,200 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का भी उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य में महिलाओं की सहायता के लिए पांच सौर पार्कों का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को मान्यता दी।

वित्तीय तनाव के बीच कैबिनेट ने दैनिक गाय सब्सिडी को बढ़ाकर ₹50 कर दिया।

एक महत्वपूर्ण कदम में, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गौशालाओं में गायों के लिए दैनिक सब्सिडी ₹30 से बढ़ाकर ₹50 प्रति गोजातीय कर दी है। अन्य राज्यों में इसी तरह की योजनाओं से मेल खाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा शुरू में प्रस्तावित, सब्सिडी वृद्धि से पहले से ही कर्ज में डूबे राज्य पर सालाना 230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है।

जिस पर अनुमानित 7.82 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। प्रति गाय ₹30 के मूल प्रस्ताव से सालाना ₹95 करोड़ की बचत होती।

यह निर्णय राज्य भर में 1.23 लाख से अधिक गोवंश की देखभाल करने वाली 828 गौशालाओं को प्रभावित करता है और इसे आगामी चुनावों से पहले अपने हिंदुत्व रुख को मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसके अनुरूप, कैबिनेट ने गायों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें "राज्यमाता-गोमाता" का दर्जा भी प्रदान किया।

हालाँकि वित्त और योजना विभागों ने मौजूदा योजनाओं का हवाला देते हुए वित्तीय तनाव के बारे में चिंता जताई, जो पहले से ही गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान प्रदान कर चुके हैं, कैबिनेट निर्णय के साथ आगे बढ़ी। यह वृद्धि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों की प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, जहां समान सब्सिडी लागू है।

महाराष्ट्र ने चुनाव पूर्व कदम में स्वदेशी गायों को 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित किया।

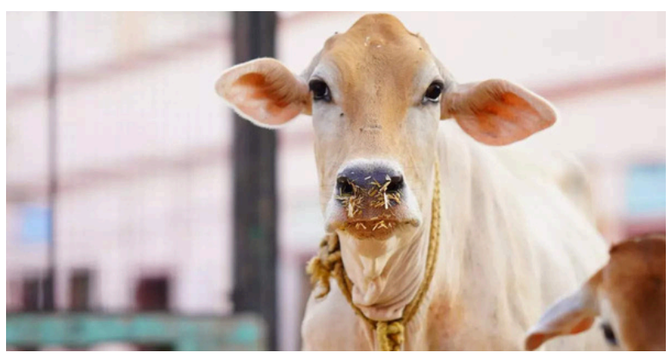

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रतीकात्मक निर्णय में, राज्य सरकार ने स्वदेशी गाय नस्लों को 'राज्यमाता-गोमाता' (राज्य गाय माता) का दर्जा दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल के नेतृत्व में यह कदम भारतीय परंपरा में देशी गायों के सांस्कृतिक और कृषि महत्व पर प्रकाश डालता है।

यह निर्णय वैदिक संस्कृति में गायों के महत्व, दूध उत्पादन में उनके पोषण मूल्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा और जैविक कृषि पद्धतियों में गाय के गोबर और मूत्र की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

राज्य के कृषि, डेयरी विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि स्वदेशी गायों को उनके आध्यात्मिक और व्यावहारिक योगदान के लिए लंबे समय से सम्मानित किया गया है। उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देशी गायें किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं और गौशालाओं के लिए समर्थन बढ़ाकर उनके कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस कदम को ग्रामीण समुदायों के बीच अपना समर्थन मजबूत करने और चुनावों से पहले हिंदुत्व भावनाओं को आकर्षित करने के सत्तारूढ़ सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, कैबिनेट ने ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए मराठा समुदाय की चल रही मांगों को संबोधित करते हुए, कुनबी-मराठा प्रमाण पत्र जारी करने पर न्यायमूर्ति शिंदे समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।

महाराष्ट्र ने मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए ₹149 करोड़ की दुग्ध विकास परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया।

महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की आय बढ़ाने और दूध उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ₹149 करोड़ के बजट के साथ दुग्ध विकास परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। 2026-27 तक चलने वाली इस परियोजना का लक्ष्य 19 जिलों में किसानों को लगभग 13,400 गाय और भैंस वितरित करना है।

क्षेत्र के किसान लाभ को लेकर आशान्वित हैं। छत्रपति संभाजीनगर के किसान सुनील पवार ने कहा कि कृषि को प्रभावित करने वाले अप्रत्याशित मानसून पैटर्न के कारण डेयरी विकास एक प्राथमिक व्यवसाय बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्र मुद्रास्फीति की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

परियोजना का कुल व्यय ₹328.42 करोड़ है, जिसमें वित्तीय बोझ का एक हिस्सा किसानों द्वारा वहन किया गया है। यह पहल कृत्रिम गर्भाधान और आईवीएफ तकनीकों के माध्यम से पशुधन की गुणवत्ता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण चारे, संतुलित आहार और पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने पर भी केंद्रित है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए निर्धारित है, जो कृषि संवेदनशीलता का सम्मान करते 2016 में शुरू किए गए पहले चरण से 11 जिलों को लाभ हुआ और इस विस्तारित चरण से मराठवाड़ा और विदर्भ में डेयरी फार्मिंग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, राज्य मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा में दान की गई और धार्मिक संस्थानों की भूमि के पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दे दी, जिससे 42,710 हेक्टेयर भूमि मालिकों के लिए लेनदेन की शर्तें आसान हो गईं।

अमेरिका में सफलता के बाद AMUL यूरोपीय बाजार में प्रवेश के लिए तैयार: एमडी

भारत का प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड AMUL, संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के बाद यूरोपीय बाजार में विस्तार करने के लिए तैयार है। गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने 11वें डॉ. वर्गीज कुरियन मेमोरियल ओरेशन के दौरान दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए इस रणनीतिक कदम की घोषणा की।

मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि एएमयूएल का मिशन व्यवसाय से परे, ग्रामीण भारत में लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका के रूप में सेवा प्रदान करना है। उन्होंने एक सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए एएमयूएल के संस्थापक और भारत की श्वेत क्रांति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दिवंगत डॉ. वर्गीस कुरियन को श्रेय दिया, जिसने ब्रांड के विकास को प्रेरित किया है।

वर्तमान में, AMUL प्रतिदिन 31 मिलियन लीटर से अधिक दूध एकत्र करता है और विभिन्न बाजारों में 50 से अधिक उत्पादों की बिक्री के साथ 80,000 करोड़ रुपये का कारोबार करता है। डॉ. कुरियन की बेटी निर्मला कुरियन ने अपने पिता के उस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया जिसने भारत को एक आत्मनिर्भर डेयरी पावरहाउस में बदल दिया। यूरोप में AMUL का प्रवेश इसके वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यूरोप में एएमयूएल का आसन्न प्रवेश इसकी वैश्विक विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो गुणवत्ता और स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

GATMEC
Global Agriculture, Technology Machinery Expo & Conference

ORGANISED BY
AFC INDIA LIMITED
(A Deemed Government Organisation)
Wholly Owned by NABARD, Commercial Banks & EXIM Bank

KNOWLEDGE PARTNERS
CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

10 - 12 DEC 2024 | YASHOBHOOMI (IICC), DWARKA, NEW DELHI

MEET
200+ Innovators
100+ Farming Technologist
50+ Machinery Solution Providers

BOOK YOUR SPACE NOW

Please contact for more information:
GATMEC Secretariat
+91 7890 561 018 info@gatmec.com
www.gatmec.com

MANAGED BY
iCONEX

GATMEC
Global Agriculture, Technology Machinery Expo & Conference

ORGANISED BY
AFC INDIA LIMITED
(A Deemed Government Organisation)
Wholly Owned by NABARD, Commercial Banks & EXIM Bank

KNOWLEDGE PARTNERS
CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

10 - 12 DEC 2024 | YASHOBHOOMI (IICC), DWARKA, NEW DELHI

सीईएएसआई-गतिविधियाँ

डेयरी में महिलाओं को सशक्त बनाना: आईटीसी और उत्कृष्टता केंद्र ने इंदौर में पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

भारत में डेयरी कौशल उत्कृष्टता केंद्र ने आईटीसी लिमिटेड के सहयोग से मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़े जुगाली करने वाले पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पहल का लक्ष्य 40 चयनित लाभार्थियों, जिन्हें पशु सखी के नाम से जाना जाता है, को पशुधन प्रबंधन और टिकाऊ डेयरी प्रथाओं में आवश्यक कौशल से लैस करके सशक्त बनाना है। उद्योग विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रजनन तकनीकों को कवर करने वाली व्यावहारिक कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आईटीसी के एक प्रतिनिधि ने कहा, "स्थायी प्रथाओं और बेहतर आजीविका के लिए कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।"

यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं के कौशल को बढ़ाता है बल्कि उनके समुदायों के भीतर नेतृत्व को भी बढ़ावा देता है, जिससे वे स्थानीय डेयरी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हो जाती हैं। कौशल विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर, यह पहल भारत भर में इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है, जो कृषि परिदृश्य को बदलने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

हम कौन हैं?

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई) "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएएसआई)" के तहत काम कर रहा है, यह एक स्वायत्त संगठन है जो "**एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)**" के तत्वावधान में काम कर रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लगे किसानों, वेतनभोगी श्रमिकों, स्व-रोज़गार पेशेवरों, विस्तार श्रमिकों आदि के कौशल और क्षमता निर्माण के लिए **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई**) के तहत काम करना।

सीईएएसआई कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों का एक शीर्ष संगठन है।

- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएचएसआई)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकेनिज़शन स्किल्स इन इंडिया (सीईएफएमआई)

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

+91 7428706078

info@cedsi.in

www.cedsi.in Follow us on Facebook Cedsi Dairyskills Follow us on Twitter @CEDSI_India Follow us on Instagram @cedsi_india Follow us on linkedin Cedsi dairy COE

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

Corporates/ Cooperatives | NGO's/CSR Foundations | Dairy Farmers | Students | Professional

www.cedsi.in

17th July 2024

@cedsi_india

CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया